

भारतीय पुनर्वास परिषद्

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार

दो दिवसीय पश्चिमी क्षेत्र के पाठ्यक्रम समन्वयकों की बैठक का संक्षिप्त विवरण-2020

भारतीय पुनर्वास परिषद्, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा **दो दिवसीय पश्चिमी क्षेत्र पाठ्यक्रम समन्वयकों की बैठक का-2020 का आयोजन 21-22 फरवरी, 2020 को बीएसएनएल ऑडिटोरियम, आरटीटीसी, नागपुर** में किया गया। जिसका उद्देश्य सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रक्रिया और विशेष शिक्षा और विकलांगता पुनर्वास पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने और सी.आर.ई., सी.आर.आर आदि के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना था।

बैठक का शुभारम्भ भारतीय पुनर्वास परिषद् के **सदस्य सचिव डॉ० सुबोध कुमार** द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान विशिष्ट अतिथि डॉ० हिमांशु दास, डॉ० राजीव जलवी, ए.वई.जे.एन.आई.एस.एच.डी., मुंबई, डॉ० जसमेर सिंह, सहायक प्राध्यापक, एन.आई.ई.पी.वी.डी., देहरादून, डॉ० गुरुबक्श जगोता, निदेशक, सी.आर.सी, नागपुर, डॉ० राजेश वर्मा, सहायक निदेशक, आर.सी.आई, डॉ० संदीप तांबे, सहायक निदेशक, आर.सी.आई. श्री संदीप ठाकुर, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं श्री संजय कुमार मित्तल, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित पश्चिमांचल क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम समन्वयक, समन्वयक (आंचलिक समन्वयक समिति) और एन.आई.ई.पी.एम.डी., चेन्नई और सी.आर.सी. नागपुर के अधिकारियों सहित 122 प्रतिभागियों ने छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से भाग लिया।

डॉ० सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद् ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में परिषद् की भूमिका, कार्यों एवं उत्तरदायित्व पर जोर दिया जो विशेष शिक्षा और विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित से सम्बंधित है। उन्होंने आग्रह किया कि परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने संस्थानों द्वारा गुणवत्तापरक मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए गैर-उपस्थित प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया एवं दो दिनों में पाठ्यक्रम समन्वयक और परिषद् के अधिकारियों के मध्य बहुत ही फलदायी परिचर्चा की अपेक्षा जिसके फलस्वरूप परिषद् को अपने विभिन्न पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों के मौजूदा मानदंडों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करने में सहायता होगी।

डॉ० हिमांशु दास, निदेशक, एन.आई.ई.पी.एम.डी., चेन्नई ने उल्लेख किया कि यह बैठक फलदायी परिणाम लाएगी और पश्चिमी क्षेत्र में आर.सी.आई. की गतिविधियों को नया आयाम देने और उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक होगी। अंत में उन्होंने बैठक की सफलता की कामना की ।

बैठक के दौरान, सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम, सी.आर.आर., सी.आर.ई., पाठ्यक्रम अनुमोदन आदि से संबंधित छह तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया । जिसके दौरान परिषद् के सहायक निदेशकों द्वारा सम्बंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया। इसी दौरान खुली परिचर्चा का आयोजन भी किया गया जिसमें परिषद् के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए कई सिफारिशें भी की गईं।

नागपुर में आयोजित यह बैठक सभी उपस्थित पाठ्यक्रम समन्वयको एवं संकायों के लिए लाभप्रद रही। इस बैठक में चर्चा किये गए सभी विषय समय की आवश्यकतानुसार थे एवं प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं से ऐसा परिलक्षित हुआ कि उनके अन्दर इन विषयों से सम्बंधित अच्छी समझ विकसित हुई जिसे वह अपने संबंधित प्रशिक्षण संस्थान(ओं) में लागू करने के इच्छुक दिखे। बैठक के दौरान आई सिफारिश को लागू करने का परिषद् हर संभव प्रयास करेगी।

(डॉ० सुबोध कुमार)
सदस्य सचिव
